नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 07
दि. 07.10.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

समुद्र में उतरा आईएनएस 'एंड्रोथ', दुश्मनों की पनडुब्बियों को पलक झपकते मिटा देगा भारत का यह स्वदेशी युद्धपोत

विशाखापत्तनम। भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूत करते हुए सोमवार को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस एंड्रोथ को शामिल कर लिया। यह पोत एक एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है, जिसे खास तौर पर उथले समुद्री इलाकों में छिपी दुश्मन पनडुब्बियों को ढूंढकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्वदेशी युद्धपोत के शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ है।

आईएनएस एंड्रोथ को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में एक भव्य समारोह के दौरान पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर की मौजूदगी में नौसेना में कमीशन किया गया। समारोह में जीआरएसई (गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स) के अधिकारियों, नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों ने हिस्सा लिया। यह पोत भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन की एक नई मिसाल माना जा रहा है।

आईएनएस एंड्रोथ की सबसे खास बात यह है कि इसमें 80 फीसदी से अधिक स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। 77 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा यह पोत लगभग 1500 टन वजन का है और 46.3 किलोमीटर प्रति घंटा (लगभग 25 नॉट्स) की रफ्तार से समुद्र में दौड़ सकता है। इसमें 30 मिमी गन और दो 12.7 मिमी रिमोट कंट्रोल मशीन गनें लगी हैं, जो इसे दुश्मन की नावों, ड्रोन और तटीय खतरों से निपटने में सक्षम बनाती हैं। यह युद्धपोत पूरी तरह से अत्याधुनिक सोनर सिस्टम, डेप्थ चार्ज, और टॉरपीडो लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। ये सभी उपकरण इसे समुद्र के भीतर छिपे दुश्मनों की हलचल को पहचानने, उनका पीछा करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें पलभर में नष्ट कर देने में सक्षम बनाते हैं।

आईएनएस एंड्रोथ में आधुनिक संचार और नियंत्रण प्रणालियां लगी हैं जो इसे लंबे समय तक उथले जल में भी प्रभावी संचालन करने की क्षमता देती हैं। यह न सिर्फ दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा कर सकता है बल्कि समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव कार्य, और तटीय रक्षा मिशनों को भी अंजाम देने में सक्षम है। कोलकाता के जीआरएसई शिपयार्ड में बने इस युद्धपोत का निर्माण पूरी तरह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। यह 'मेक इन इंडिया' पहल की एक बड़ी सफलता का प्रतीक है। आईएनएस एंड्रोथ का नाम लक्षद्वीप समूह के उत्तरी द्वीप एंड्रोथ के नाम पर रखा गया है, जो भारतीय समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने जहाज के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करते हुए इसे नौसेना की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि "आईएनएस एंड्रोथ भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता का सजीव उदाहरण है। यह न केवल तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक बढ़त को और सुदृढ़ करेगा।"

वर्तमान में भारत के पास 100 से अधिक सक्रिय युद्धपोत हैं और आईएनएस एंड्रोथ के शामिल होने से यह संख्या और सशक्त हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह छोटा लेकिन बेहद घातक युद्धपोत आने वाले वर्षों में तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियानों में भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। समुद्र में दुश्मन की हर हरकत को सूंघने और उसे तबाह करने की ताकत रखने वाला आईएनएस एंड्रोथ अब भारतीय नौसेना के बेड़े में वह नया प्रहरी बन गया है, जो भारत के समुद्री सीमाओं की रक्षा में 24 घंटे मुस्तैद रहेगा।

नाशिक में दादासाहेब फालके फिल्म सिटी बनेगी, महाराष्ट्र को मिलेगा नया मनोरंजन केंद्र

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने नाशिक में एक अत्याधुनिक फिल्म सिटी स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। सोमवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस परियोजना की रूपरेखा और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। पवार ने कहा कि राज्य सरकार नाशिक में फिल्म सिटी बनाने के लिए पूरी तरह सकारात्मक है और विशेषज्ञ सलाहकार समिति की रिपोर्ट मिलते ही उसकी व्यवहार्यता जांचकर तत्काल प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 'वैश्विक मनोरंजन केंद्र' बनाने का जो सपना देखा है, उसे साकार करने में महाराष्ट्र की भूमिका अग्रणी होगी। अजित पवार ने बताया कि नाशिक की यह फिल्म सिटी राज्य के मनोरंजन, रोजगार और पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों, लघु उद्योगों, होटल व्यवसाय, परिवहन और सेवा क्षेत्र में व्यापक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे न केवल नाशिक की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि शहर सांस्कृतिक दृष्टि से भी अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि दादासाहेब फालके की जन्मभूमि होने के कारण नाशिक इस परियोजना के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त स्थान है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म सिटी नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की जड़ों से जुड़ी एक सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जीवन का प्रयास होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुंभ मेले के लिए बनी उच्चस्तरीय आधारभूत सुविधाएं इस परियोजना के लिए उपयोगी साबित होंगी, जिससे निर्माण लागत भी काफी हद तक कम हो जाएगी। राज्य अतिथिगृह 'सह्याद्री' में हुई इस बैठक में मंत्री छगन भुजबल, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार (ऑनलाइन माध्यम से), अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, प्रधान सचिव विकास खारगे, उद्योग विभाग की सचिव किरण कुलकर्णी और पर्यटन विभाग की निदेशक स्वाति म्हसे-पाटील समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं नाशिक प्रशासन के अधिकारी और फिल्म जगत से जुड़े कई प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल हुए। अजित पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद व्यवहार्यता अध्ययन (फीजिबिलिटी रिपोर्ट) को तेजी से पूरा किया जाए और सभी आवश्यक मंजूरियां जल्द से जल्द प्राप्त कर परियोजना को प्रारंभिक स्तर पर लागू किया जाए।

सरकार का बड़ा फैसला: 10 साल बाद बदली गई सीजीएचएस दरें, 46 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी राहत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक दशक बाद केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) में बड़ा बदलाव करते हुए दरों में संशोधन का ऐतिहासिक फैसला लिया है। नई दरें 13 अक्टूबर से पूरे देश में लागू होंगी। इस निर्णय से लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिजन सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

सरकार ने पहली बार अस्पतालों की श्रेणी, शहरों की श्रेणी और वार्ड टाइप के अनुसार इलाज की दरों को पुनर्गठित किया है। औसतन दरों में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, जिससे अब निजी अस्पतालों को भी योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे संशोधित दरों को स्वीकार करें, अन्यथा उन्हें सीजीएचएस पैनल से हटाया जाएगा।

पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह शिकायत आम थी कि निजी अस्पताल कैशलेस इलाज देने से इंकार कर देते हैं। मरीजों को पहले पूरा भुगतान करना पड़ता था और फिर महीनों बाद प्रतिपूर्ति मिलती थी। दूसरी ओर, अस्पतालों का तर्क था कि सीजीएचएस की पुरानी दरें मौजूदा चिकित्सा खर्चों के मुकाबले बहुत कम थीं, जिससे उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ता था।

आखिरी बार इस योजना में व्यापक संशोधन साल 2014 में हुआ था। उसके बाद से सिर्फ आंशिक सुधार किए गए थे, लेकिन अस्पताल सेवाओं, दवाओं, जांच और पैकेज की बढ़ती लागत के कारण अब यह सुधार अपरिहार्य माना जा रहा था।

कर्मचारी यूनियनों का भी इस फैसले में बड़ा योगदान रहा। नेशनल फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन्स ने अगस्त में सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा था कि कैशलेस सुविधा न मिलने के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के बाद केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे पर त्वरित निर्णय लिया।

नई दरों से उम्मीद की जा रही है कि निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा फिर से सुचारू होगी, मरीजों को वित्तीय राहत मिलेगी और उपचार की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के बीच केंद्र की योजनाओं के प्रति विश्वास और संतोष भी मजबूत करेगा।

लोकतंत्र का महापर्व: छठ के बाद सजेगा चुनावी संग्राम, बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव, 14 नवंबर को आएगा परिणाम

पटना। बिहार की राजनीतिक जमीन एक बार फिर गर्माने जा रही है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार राज्य में मतदान दो चरणों में होगा — पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को, जबकि मतगणना और परिणाम की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी। विशेष बात यह है कि इस बार का चुनाव महापर्व छठ के आठ दिन बाद होने जा रहा है, जिससे यह चुनाव सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से ऐतिहासिक बन गया है। यह 40 साल बाद होगा जब बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा। पिछली बार 1985 में दो-चरणीय मतदान हुआ था, जब कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और राज्य में एक ही कार्यकाल में चार मुख्यमंत्री बदल गए थे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा — मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर।

वहीं दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें शामिल हैं — पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। इस तरह बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। इनमें 203 सामान्य सीटें, 38 अनुसूचित जाति (एससी) और 2 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं। बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी।

7.42 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान

इस बार के चुनाव में कुल 7.42 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिलाएं और 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि 14 लाख युवा पहली बार मतदान करेंगे। वहीं 4.04 लाख वरिष्ठ नागरिक 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि 14 हजार मतदाता शतायु (100 वर्ष से अधिक) हैं। इसके अतिरिक्त 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता और 1.63 लाख सेवा में कार्यरत मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं में सर्वाधिक संख्या 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की है, जिनकी कुल संख्या 1.63 करोड़ है।

चुनाव आयोग की तैयारी पूरी

राज्य में कुल 90,712 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 13,911 शहरों में और 76,801 गांवों में स्थित हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर औसतन 818 वोटर होंगे। महिलाओं द्वारा संचालित 1,044 पोलिंग स्टेशन और युवाओं द्वारा प्रबंधित 38 स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 1,350 मॉडल बूथों की भी व्यवस्था की गई है।

पहले चरण की तारीखें

- नोटिफिकेशन जारीः 10 अक्टूबर
- नामांकन की अंतिम तिथिः 17 अक्टूबर
- नामांकन पत्रों की जांचः 18 अक्टूबर
- नाम वापसी की तिथिः 20 अक्टूबर
- मतदानः 6 नवंबर

दूसरे चरण की तारीखें

- नोटिफिकेशन जारीः 13 अक्टूबर
- नामांकन की अंतिम तिथिः 20 अक्टूबर
- नामांकन पत्रों की जांचः 21 अक्टूबर
- नाम वापसी की तिथिः 23 अक्टूबर
- मतदानः 11 नवंबर

राजनीतिक समीकरणों का संग्राम शुरू

बिहार की वर्तमान राजनीति में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन (जेडीयू-भाजपा) और विपक्षी महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस-वामदल) के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। मौजूदा विधानसभा में भाजपा के पास 80, आरजेडी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19 और शेष सीटें छोटे दलों के पास हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार पूर्ण बहुमत के लक्ष्य के साथ मैदान में हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अब तक के सबसे कठिन चुनावी इम्तिहान से गुजरेंगे।

40 साल बाद फिर दो-चरणीय चुनाव का इतिहास दोहराएगा बिहार?

1985 के चुनाव में दो चरणों में मतदान हुआ था, और तब कांग्रेस ने 196 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद बिहार की राजनीति ने कई करवटें लीं — समाजवाद का उदय हुआ, लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में प्रवेश किया, और फिर नीतीश कुमार ने विकास के मुद्दे पर राजनीति को नई दिशा दी। अब 2025 में फिर से दो चरणों वाला चुनाव बिहार के राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रहा है।

छठ के बाद जब बिहार के घाटों पर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लोग अपने गांव लौटेंगे, उसी दौरान लोकतंत्र का यह पर्व पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाएगा। इस बार का चुनाव न केवल सत्ता का परिवर्तन तय करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि बिहार की जनता विकास, युवाओं, और सामाजिक न्याय के किस रास्ते को चुनती है।

बीजेपी में राष्ट्रीय और यूपी अध्यक्ष पद पर बड़ा मंथन, संघ की 'सहमति' के बाद ही होगा फाइनल फैसला

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से चल रहा मंथन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अब तक नामों और संभावित उम्मीदवारों पर विचार-मंथन पूरा कर लिया गया है, लेकिन किसी भी नाम की आधिकारिक घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही की जाएगी। यह कदम राजनीतिक संतुलन, रणनीति और आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी जा सकती है, जबकि यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर ओबीसी नेता के नाम पर दांव लगाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी ने इससे पहले गुजरात और झारखंड के प्रदेश अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्षों के नाम आने वाले दिनों में घोषित किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय और यूपी अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के वर्तमान सक्रिय नेताओं, वरिष्ठ नेताओं और हाल ही में नियुक्त चुनाव प्रभारियों की राय भी ली गई है। दक्षिण भारत के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह स्वयं इस पद के लिए "सक्षम" नहीं हैं, जबकि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 60 वर्ष के आसपास उम्र वाला नेता होना चाहिए, ताकि अनुभव और ऊर्जा का संतुलन बना रहे।

बीजेपी और संघ के संबंधों पर चर्चा करते हुए पार्टी सूत्रों ने बताया कि सरकार और संगठन अलग-अलग ढांचे हैं। सरकार में संघ का दखल नहीं होता, लेकिन संगठन में नेतृत्व देने के लिए संघ की सहमति लेना जरूरी है। यही कारण है कि राष्ट्रीय और यूपी अध्यक्ष पदों पर किसी भी नाम को अंतिम रूप देने से पहले संघ का विश्वास लेना अनिवार्य माना जा रहा है।

यूपी की सियासी पृष्ठभूमि के अनुसार, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रीय समुदाय से आते हैं। ऐसे में पार्टी संभावना जता रही है कि प्रदेश अध्यक्ष पद ओबीसी नेता को सौंपा जा सकता है। वहीं, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण नेता को कमान देने की दिशा में चर्चा चल रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी इस बार संघ और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संतुलित निर्णय लेने पर जोर दे रही है। पार्टी की यह रणनीति न केवल आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बैंक को मजबूत करेगी, बल्कि संगठनात्मक ढांचे को भी प्रभावी बनाए रखने में मदद करेगी।

कुल मिलाकर, राष्ट्रीय और यूपी अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी का मंथन अब अंतिम चरण में है और संघ की सहमति मिलने के बाद ही पार्टी अपने फैसले का ऐलान करेगी। यह फैसला आगामी राजनीतिक परिदृश्य और पार्टी की रणनीति को नई दिशा देगा।

कटक हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू, आठ गिरफ्तार – तनाव के बीच शांति की अपील

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने नाशिक में एक अत्याधुनिक फिल्म सिटी स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। सोमवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस परियोजना की रूपरेखा और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। पवार ने कहा कि राज्य सरकार नाशिक में फिल्म सिटी बनाने के लिए पूरी तरह सकारात्मक है और विशेषज्ञ सलाहकार समिति की रिपोर्ट मिलते ही उसकी व्यवहार्यता जांचकर तत्काल प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 'वैश्विक मनोरंजन केंद्र' बनाने का जो सपना देखा है, उसे साकार करने में महाराष्ट्र की भूमिका अग्रणी होगी। अजित पवार ने बताया कि नाशिक की यह फिल्म सिटी राज्य के मनोरंजन, रोजगार और पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों, लघु उद्योगों, होटल व्यवसाय, परिवहन और सेवा क्षेत्र में व्यापक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे न केवल नाशिक की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि शहर सांस्कृतिक दृष्टि से भी अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि दादासाहेब फालके की जन्मभूमि होने के कारण नाशिक इस परियोजना के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त स्थान है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म सिटी नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की जड़ों से जुड़ी एक सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जीवन का प्रयास होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुंभ मेले के लिए बनी उच्चस्तरीय आधारभूत सुविधाएं इस परियोजना के लिए उपयोगी साबित होंगी, जिससे निर्माण लागत भी काफी हद तक कम हो जाएगी। राज्य अतिथिगृह 'सह्याद्री' में हुई इस बैठक में मंत्री छगन भुजबल, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार (ऑनलाइन माध्यम से), अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, प्रधान सचिव विकास खारगे, उद्योग विभाग की सचिव किरण कुलकर्णी और पर्यटन विभाग की निदेशक स्वाति म्हसे-पाटील समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं नाशिक प्रशासन के अधिकारी और फिल्म जगत से जुड़े कई प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल हुए। अजित पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद व्यवहार्यता अध्ययन (फीजिबिलिटी रिपोर्ट) को तेजी से पूरा किया जाए और सभी आवश्यक मंजूरियां जल्द से जल्द प्राप्त कर परियोजना को प्रारंभिक स्तर पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिटी आने वाले समय में न केवल महाराष्ट्र, बल्कि पूरे भारत के फिल्म उद्योग के लिए नई पहचान बनेगी और भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर और ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

संपादकीय

हर क्राइम में फिर भी ज़िंदा है रावण

रावण का निपटारा हो गया, पर क्या रावण का निपटारा कभी हो पाया है? सिमी ग्रेवाल सीनियर एक्ट्रेस ने कहा कि रावण खराब नहीं, बस शरारती है। सो रावण ने कई जगह जलने से इनकार कर दिया। कई शहरों में बारिश आ गयी, रावण जला नहीं, बारिश में गला, धुला।

अगली बार से रावण-दहन के साथ रावण-धुलन की तैयारी होगी। जलने से इनकार पर रावण बोला—अब बुराई जलती नहीं, ट्रेंडिंग हो जाती है, सोशल मीडिया पर।

Advertisement

ट्रॉफी दबाने वाले पाक नेता मोहसिन नकवी की हरकतों पर रावण बोला—दूसरों का माल किडनैप करने वाले अपनी टीम का नाम रावण राइडर्स रखें, इससे उनकी आईपीएल से जुड़ने की इच्छा भी पूरी हो लेगी।

Advertisement

वैसे सच यह है कि कई बॉस अपने कर्मचारियों को रावण के तौर पर देखना चाहते हैं। एक सिर से ईमेल लिखें, दूसरे सिर से प्रजेंटेशन बनायें। तीसरे सिर से चमचागिरी करें, चौथे सिर से विरोधियों की चुगली करें। वक्त बहुत ही टेक्निकल हो गया है। नये बच्चों का मिजाज बिलकुल ही सोशल मीडियाना हो गया है। अब अगर रावण मरता तो बेटा उसकी मौत पर सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल कर रहा होता— 'पापा अब नहीं रहे... लेकिन राख से भी उठेगा ब्रांड # रावण। रावण परिवार खैर मना रहा होता है कि रावण ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया पर।

रावण खुद कैंपेन चलवा रहा होता सिम्मी ग्रेवाल के बयान का सहारा लेकर कि मैं सिर्फ नॉटी हूं, खराब नहीं। खैर, रावण मरा नहीं है, ट्रेंडिंग हो गया है-बर्निंग सिन्स त्रेता युग।

वक्त यह है कि अब रावण खुद-ब-खुद ट्रेंड करने लगता है। रावण तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता, कहता कि मुझे देखिये, हर साल मारा जाता हूं, लतियाया जाता हूं, फिर भी दोबारा आ जाता हूं। तो जमे रहिये। एक बात पक्की है कि रावण हमारे वक्त में होता तो बहुत ही बड़ा मीडिया इन्फ्लूएंसर होता।

10 सिर, मतलब 10 अकाउंट्स।

एक सिर से इंस्टाग्राम रील बनाता—'अयोध्या जा रहा हूं भाई लोग, कुछ बड़ा होने वाला है!'

दूसरे सिर से ट्विटर पर लिखता—'# बायकाट वानर सेना।'

अगर आज रावण राजनीति में होता, तो पक्का कोई पार्टी बना चुका होता—'लंका जनता मोर्चा' या 'रावण राष्ट्र दल।'

रावण कहता, 'देखिए, मैं विलेन नहीं हूं, गलत समझा गया नेता हूं। और रावण के पास बहुत समर्थक भी हो जाते। अब समर्थन सही-गलत देखकर नहीं दिया जाता। समर्थन बस यह देखकर दिया जाता है कि इससे अपना फायदा है या नहीं। रावण के लिए सबसे सही वक्त वैसे अभी का ही था। रावण अब तक टीवी चैनलों को टीआरपी दिलवाता है। कई चैनल तो रावण को मरने ही नहीं देते। क्राइम की खबरें बहुत देखी जाती हैं। रावण हर क्राइम में जिंदा है जी।

अपने ज़ुबिन के लिए न्याय चाहता है असम

> "ज़ुबिन गर्ग के रूप में असम की आवाज, जो खामोश हो गई है, लेकिन उनके गीत कानों में गूंजते रहेंगे। असमिया संगीत जगत के गायक सुपरस्टार का आम लोगों के साथ अनोखा जुड़ाव था। वह शासन की बेबाक आलोचना के लिए विख्यात थे। युवा पीढ़ी रूढ़िवाद को धत्ता बताने के ज़ुबिन के अंदाज़ से सम्मोहित थी।

असम की राजधानी गुवाहाटी से कुछ ही दूरी पर एक गांव में, जो सांस्कृतिक प्रतीक बन गए 21 वर्षीय युवा ज़ुबिन गर्ग का पैतृक ग्राम है, जब उसकी चिता को रोते-सुबकते लोगों के विराट समूह के बीच अग्नि भेंट किया गया तो आसमान 21 राइफल की सलामी फायरिंग से गूंज उठा। इससे पूर्व भूपेन हज़ारिका को 2021 में ऐसा राजकीय सम्मान मिला था।

ज़ुबिन के लिए तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया। जैसे-जैसे आग की लपटें बढ़ती गईं, लाखों प्रशंसक उनकी 'मायाबिनी' के सामूहिक गीत गाते रहे। इस गीत का सार उनके कई अन्य गीतों की तरह न केवल इस गायक सुपरस्टार के शब्दों का जादू लिए था, बल्कि असमिया और गैर-असमिया की पीढ़ियों के साथ उनके अनोखे जुड़ाव को दर्शाता है। गीत के बोल हैं 'इस जादुई रात के बीचोंबीच, मैं दूर से तुम्हारा चेहरा पहचान सकता हूं। तुम चुपचाप मेरे दिल के किसी कोने में समा गए हो, मेरे मुरझाए मन पर ओस की एक ताज़ा बूंद की तरह, चमकती धूप के जैसे, वर्ना तो, मैं बरसों तक तूफ़ान के भंवर में रहा, यूं अंधेरे से मेरी दोस्ती बहुत पहले हो चुकी थी।'

किशोरावस्था में ही ज़ुबीन अपनी पहली एल्बम के साथ असमिया संगीत जगत पर छा गए। हज़ारिका जैसे महान कलाकार की लोक एवं शास्त्रीय संगीत के सम्मिश्रण वाली मौलिक बंदिशें सुनने के आदी श्रोताओं के लिए ज़ुबीन की आवाज़ ताज़गी लिए रही। वो नियम का एक अपवाद थे। उन्होंने गायकी के किसी नियम का पालन नहीं किया, अपने बनाए संगीत, पटकथा पर पेशकारी से जीते-जी किंवदंती बन गए। ज़रा सोचिए, करीब 40 भाषाओं में 35,000 गाने- उनमें एक था फिल्म गैंगस्टर का 'या

अली', जिसने उन्हें बॉलीवुड में प्रसिद्धि दिलाई, ऐसी जगह जिसके लिए उन्होंने घर आना छोड़ दिया था। उम्र सिर्फ़ 52 साल रही। अपने विशिष्ट अंदाज़ में उन्होंने अपना समर्पित प्रशंसक वर्ग अर्जित कर लिया था। खासकर युवाओं के बीच, जो रूढ़िवाद और पूर्वाग्रहों को धत्ता बताने के ज़ुबिन के तरीके से सम्मोहित थी, उनके जोशीलेपन और आमजन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग से भी, राजनीति और राजनेताओं का मखौल बनाने से, बच्चों के साथ मंच पर गाते-गाते उनकी तरह नाचने पर, मदद मांगने वालों के प्रति उदारता से, जानवरों एवं पेड़ों के प्रति प्रेम पर और बड़ा सितारा होने के बावजूद लोगों के लिए उनकी सुलभता से वे मंत्रमुग्ध थे। इन सबके बीच, असमिया संस्कृति और लोगों के प्रति उनका प्रेम चमकता रहा, जिसका वे जमकर बचाव करते और खुलकर प्रदर्शन करते।

असम से बाहर के कई मीडिया टिप्पणीकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों के लिए, न केवल गुवाहाटी में बल्कि असम के गांवों-कस्बों की सड़कों पर उनके गीत गुनगुनाते, रोते या आंसू थामने की कोशिश करते लोगों के विशाल सागर को देखना हैरानीजनक रहा व पूछने लगे—उनके अविश्वसनीय आकर्षण की व्याख्या क्या है? अपने लोगों के दिलो-जान में इस कदर कैसे समा गए? इसके अनेक जवाब हैं और शायद कई साल बाद भी हम इसका कोई एक सटीक जवाब न दे पाएं। उनका जादू धर्म, जातीयता, भाषा व क्षेत्र से परे था, जिनका प्रयोग कई राजनेता लोगों को बांटने और घृणा व सांप्रदायिकता भड़काने को करते रहे।

ज़ुबीन, उनके गीतों, संगीत और संदेशों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया से, असम के लोगों का उनको श्रद्धांजलि देने को इतनी बड़ी तादाद में उमड़ना पुष्टि करता है कि विभाजन और विखंडन के प्रयासों के बावजूद उनके संगीत ने असम को कलह के वक्त भी बांधे रखा, उस पर मरहम का काम किया। उनके बोल युवाओं और मध्यम उम्र के लोगों व वृद्धों के दिलों को छूते, वे सब जो अनिश्चित और असुरक्षित समय से जूझ रहे, अपने भविष्य को लेकर चिंतित, हिंसा-हानि, सशस्त्र आंदोलनों व सत्ता से परेशान हैं, वे सब चीज़ें जिन्होंने उनकी भूमि और समाज को बर्बाद कर रखा है। ज़ुबिन ने अपने बोलों से उनकी आलोचना करने में कसर नहीं छोड़ी। जब सशस्त्र गुट उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) ने असम के बिहू उत्सव समारोहों में हिंदी गीतों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, तो उन्होंने इसकी निंदा की व कहा कि वे ऐसी सांस्कृतिक दबंगई से विचलित नहीं होंगे।

वे राजनेताओं, मंत्रियों का मज़ाक उड़ाते, और एक बार मुख्यमंत्री तक से पूछा, जिन्होंने ज़ुबिन की तरह मंच पर छलांग लगाकर चढ़ते हुए तस्वीरें छपवाईं, 'आप मेरी नकल क्यों कर रहे हैं?' उनके फॉलोअर्स को उनका यह मनमौजी, कटाक्ष युक्त हास्य और बेबाक रंग-ढंग खूब जंचा। इंस्टाग्राम पर 1.28 मिलियन फॉलोअर्स और लोगों के दिलोदिमाग पर किसी राजनेता से कहीं अधिक पकड़ के साथ, उनका रुतबा बहुत बड़ा था। हालांकि राजनीति में नहीं थे तथापि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध कर अपना दृष्टिकोण जाहिर किया और समाजवाद में अपने विश्वास को व्यक्त करते रहते। बताया कि कैसे उन्होंने कभी भाजपा का समर्थन किया था क्योंकि तब लोग असम में 'पोरीबोर्तन' चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उनमें कमियां नहीं थीं, कुछ कमजोरियां जिन्हें खुद खुलकर स्वीकार किया। मेरे (लेखक के) चचेरे भाई, 'डी'कॉम भुयान, जो ज़ुबीन के साथ काम करते थे और अच्छी तरह जानते थे, उनकी अदम्य इच्छाशक्ति के बारे में लिखते हैं 'वे अथक थे। उनके शरीर पर नील पड़ जाते थे, उनका कार्यक्रमों का दबाव बेहद था, फिर भी तत्परता मानो दिव्य जैसी। जहां अधिकांश लोग थकावट या व्यावहारिकता का हवाला देकर हार मान लेते वहीं ज़ुबीन ऐसा नहीं करते। वे तूफ़ान में जीते थे। ऐसी ही एक नींद-विहीन शूटिंग के बाद, वे मेरी ओर मुड़े, उनकी आंखें चमक रही थीं, और मुझ से कहा—'डी'कॉम, जीवन अभ्यास के लिए नहीं बना। आप बस इससे बार-बार खेलते हैं, जब तक यह समझ न आए'। ज़ुबीन का स्वास्थ्य इतिहास यदि इसे भयावह नहीं तो भी आश्चर्यजनक तो ज़रूर बनाता है कि पूर्वोत्तर के इस एकमात्र सुपरस्टार को तथाकथित पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के लिए सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान खुले समुद्र में न सिर्फ तैरने के लिए जाने दिया बल्कि उकसाया भी गया। सिंगापुर पुलिस उनके डूबने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। असम में भी पुलिस जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत और 'उनसे जुड़े किसी संगठन को असम में किसी भी समारोह या उत्सव के आयोजन से रोकने' को काली सूची में डालने की घोषणा की है।

ज़ुबिन के दाह संस्कार के दौरान जिन शख्सियतों की छवियां गौरतलब रहीं - उनमें ज़ुबीन की पत्नी गरिमा का फूट-फूट कर रोना, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का मुश्किल से आंसू रोक पाना शामिल था। ज़ुबिन की मौत हरेक असमिया परिवार के लिए निजी क्षति है। तमाम राजनेता-सत्ताधारी हो या विपक्षी - बिना किसी द्वेष के एक साथ दाह संस्कार में मौजूद थे। अब शासन के सामने बड़ी चुनौती है : ज़ुबीन के लिए न्याय की मांग कर रहे हज़ारों लोगों की बढ़ती नाराज़गी से कैसे निबटा जाए?

प्रेरणा

चाँद की रोशनी में सजा प्रेम का अटूट व्रत — करवा चौथ की अमर कथा

भारत की सांस्कृतिक धरोहर में यदि कोई ऐसा पर्व है जो स्त्री के प्रेम, विश्वास और त्याग को साक्षात रूप में प्रस्तुत करता है, तो वह है करवा चौथ। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि वह आत्मिक उत्सव है जिसमें नारी अपने प्रेम को तपस्या में, और अपने विश्वास को पूजा में बदल देती है। यह दिन भारतीय स्त्री के भीतर छिपे उस अदृश्य बल की अभिव्यक्ति है, जो सृष्टि को स्थिरता देता है और प्रेम को अमरत्व प्रदान करता है।

सुबह की पहली किरण के साथ जब सुहागिन स्त्रियाँ स्नान कर लाल चुनरी ओढ़ती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं और हाथों में मेहंदी की लाली सजाती हैं, तब उनके भीतर केवल श्रृंगार नहीं होता, बल्कि जीवन के प्रति गहरी आस्था जागृत होती है। उनके हर आभूषण, हर अलंकार में एक अर्थ छिपा होता है — मंगलसूत्र में सुरक्षा का वचन, चूड़ियों में हर्ष की ध्वनि, और बिंदी में ब्रह्मांड की ज्योति। जब वे पूजा की थाल सजाती हैं, करवा में जल भरती हैं और चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती हैं, तब वह प्रतीक्षा केवल एक क्षणिक घटना नहीं होती, वह प्रतीक्षा प्रेम के परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा होती है।

करवा चौथ की रात उस दिव्यता से भरी होती है जिसे शब्दों में बाँधा नहीं जा सकता। चाँदनी जब धरती पर उतरती है, दीपक की लौ जब हवा में थरथराती है, तब स्त्री के मन में केवल एक भावना होती है — अपने पति के जीवन की रक्षा और उसके सुख की प्रार्थना। वह अपनी थकी हुई देह के बावजूद अटूट विश्वास के साथ उस क्षण का इंतजार करती है जब चाँद आकाश में झलकेगा। और जब वह चाँद निकलता है, जब

छलनी के पार से वह अपने पति का चेहरा देखती है, तब उस क्षण में संसार थम-सा जाता है। वह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि दो आत्माओं के मिलन का प्रतीक बन जाता है — जहाँ प्रेम शब्दों से नहीं, नज़रों से प्रकट होता है।

इस पर्व की जड़ें भारतीय इतिहास और लोककथाओं में गहराई से बसी हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले वीरवती नामक एक सुहागिन ने यह व्रत किया था। परंतु उसके भाइयों ने बहन की भूख और प्यास देखकर छल से दीपक जलाकर चाँद का भ्रम पैदा किया। वीरवती ने यह समझकर कि चाँद निकल आया है, व्रत तोड़ दिया। उसी क्षण उसके पति का निधन हो गया। जब उसे सत्य का बोध हुआ, तब उसने आँसू और तप दोनों से ईश्वर को पुकारा। उसकी निष्ठा, प्रेम और प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसके पति को पुनः जीवनदान दिया। तभी से यह व्रत अमर बन गया — उस प्रेम की स्मृति में जिसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया।

प्राचीन समय में करवा चौथ केवल वैवाहिक प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि सामाजिक एकता का उत्सव भी था। जब फसलें पकने लगती थीं, तो गाँव की महिलाएँ एक-दूसरे के घर जाकर मिट्टी के करवे भेंट करती थीं। यह केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि भावनाओं का संचार था — जैसे कह रही हों, "हम सब एक हैं, हमारे घरों की लौ एक ही आस्था से जलती है।" वह करवा केवल जल का पात्र नहीं था, वह जीवन का प्रतीक था — जो सबको जोड़ने वाला सूत्र था।

आज के युग में जहाँ जीवन की गति तेज़ है और रिश्तों की गहराई कभी-कभी खो जाती है, वहाँ भी करवा चौथ का यह पर्व अपनी गरिमा और भावनात्मक ऊष्मा को बनाए हुए है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चे संबंध बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि विश्वास और त्याग से बनते हैं। जब कोई स्त्री उपवास करती है, तो वह केवल धार्मिक कर्म नहीं करती, बल्कि वह यह सन्देश देती है कि प्रेम की शक्ति आत्मा को भी अमर बना सकती है।

भारत के हर कोने में इस दिन का रंग अलग होता है। पंजाब में गीतों और ढोलक की थाप पर महिलाएँ "करवा चौथ का व्रत है आज" गाती हैं, तो राजस्थान में वे पारंपरिक परिधानों में सजकर चाँद की प्रतीक्षा करती हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के घरों में दीपों की रोशनी से आँगन जगमगाते हैं, और दिल्ली की छतों पर जब चाँद उगता है, तो लगता है मानो पूरा शहर एक ही भाव से साँस ले रहा हो। विदेशों में बसे भारतीय परिवार भी इस दिन अपने घरों में वही विधि अपनाते हैं, मानो वह अपनी मिट्टी की खुशबू को अपने साथ लेकर जी रहे हों।

'करवा' और 'चौथ' — इन दोनों शब्दों का संगम भी गहन दार्शनिकता लिए हुए है। करवा अर्थात मिट्टी का घड़ा — जो जीवन, स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक है। चौथ अर्थात चंद्रमा की चौथी तिथि — जो शीतलता, सुंदरता और शांति का प्रतीक है। जब यह दोनों एक साथ आते हैं, तो यह पर्व प्रेम और संतुलन की पूर्णता का द्योतक बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में तप और मधुरता, दोनों का संगम ही सच्चे प्रेम की पहचान है।

करवा चौथ की रात जब स्त्री दीपक जलाती है, तो वह केवल पूजा नहीं करती — वह अपने भीतर की रोशनी को जगाती है। वह उस अनंत स्त्री-तत्व को जागृत करती है जो सृष्टि का आधार है। उसके व्रत की पवित्रता यह कहती है कि प्रेम केवल पाने का नहीं, बल्कि देने का नाम है। जब वह चाँद की ओर देखती है, तो वह केवल अपने पति को नहीं, बल्कि उस शाश्वत पुरुष सिद्धांत को प्रणाम करती है जिसके बिना सृष्टि अधूरी है।

यही कारण है कि करवा चौथ भारतीय संस्कृति की आत्मा है — एक ऐसा पर्व जो समय के हर अंधकार में प्रकाश की लौ बनकर जलता है। यह हमें यह सिखाता है कि जहाँ प्रेम है, वहाँ आस्था है; जहाँ आस्था है, वहाँ जीवन है; और जहाँ जीवन है, वहाँ सृष्टि की अनवरत गति है। करवा चौथ का यह अमर पर्व हमें यह याद दिलाता है कि प्रेम और विश्वास ही वह दो दीपक हैं जो हर युग में मनुष्य के मार्ग को आलोकित करते रहेंगे।

विकास की कीमत पर मुफ्त की रेवड़ियां

भारत की राजनीति में चुनावी मौसम आते ही मुफ्त सुविधाओं और लोकलुभावन वादों की बौछार शुरू हो जाती है, जिन्हें आलोचक अक्सर 'रेवड़ियां' कहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इसी क्रम में कई योजनाओं की घोषणा की है—जिनमें महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता, बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपये की एकमुश्त राशि, मुफ्त बिजली, पेंशन में दो गुना वृद्धि और निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की सहायता राशि शामिल हैं।

इन योजनाओं पर अगले दो वर्षों में 2,800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है, जबकि बिहार का वार्षिक राजस्व लगभग 56,000 करोड़ रुपये है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस तरह की लोकलुभावन घोषणाएं राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बोझ बनेंगी, या यह सामाजिक कल्याण की दिशा में एक जरूरी कदम हैं?

बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस) के बीच कांटे की टक्कर है। नीतीश सरकार ने महिलाओं (51 प्रतिशत मतदाता) और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। 18 सितंबर को शुरू हुई 10,000 रुपये की सहायता योजना 12 लाख युवाओं तक पहुंचेगी। इसके अलावा, 1.67 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण जैसे वादे हैं। दूसरी ओर, आरजेडी ने जातिगत सर्वे के आधार पर और अधिक कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया है।

उधर, सामाजिक मंचों पर कुछ लोग इन घोषणाओं को 'वोट खरीदने की रणनीति' मानते हैं, जबकि कुछ इसे 'सामाजिक कल्याण' की दिशा में एक कदम मानते हैं। इन योजनाओं का फोकस विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और अति पिछड़ा वर्ग जैसे समुदायों पर है, जिससे राज्य की जाति-आधारित राजनीति को और गति मिलने की संभावना है।

हालांकि, ये योजनाएं अल्पकालिक रूप से मतदाताओं को आकर्षित करने में कारगर हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा दे सकती हैं और बुनियादी ढांचे तथा विकास परियोजनाओं को पीछे धकेल सकती हैं। विपक्षी दल भी अब इसी राह पर चलने लगे हैं, जिससे राज्य की राजनीति में एक तरह का 'रेवड़ी युद्ध' शुरू हो गया है—जहां नीतियों की प्रतिस्पर्धा की जगह वादों की होड़ ने ले ली है।

बिहार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। इस समय प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 40 प्रतिशत कम है और बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत के आसपास है। इन योजनाओं से राज्य के खजाने पर शुरुआत में 2,800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यदि योजनाएं स्थायी हुईं, तो कर्ज-जीएसडीपी अनुपात (वर्तमान में 36 प्रतिशत) और बढ़ेगा। उधर, मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं बिजली बोर्डों पर दबाव डालेंगी, जो पहले से घाटे में चल रहे हैं। मुफ्त बिजली से पानी और ऊर्जा का दुरुपयोग बढ़ेगा, और नकद सहायता से कार्यबल की भागीदारी कम हो सकती है। कृषि-आधारित बिहार में, जहां 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है, संसाधनों का असंतुलित आवंटन दीर्घकालिक विकास के लिए गंभीर बाधा बन सकता है। पहले से ही सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचों पर खर्च सीमित है; 'रेवड़ियों' पर बढ़ता खर्च इन जरूरी क्षेत्रों की उपेक्षा को और बढ़ा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में रेवड़ियों को 'लोकतंत्र के लिए खतरा' बताया था और विशेषज्ञ समिति बनाने का सुझाव दिया था। फिर भी, दल विकास के बजाय अल्पकालिक लाभ पर जोर दे रहे हैं। यह प्रवृत्ति जातिगत और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। बिहार में ओबीसी और दलित केंद्रित योजनाएं अन्य राज्यों में भी ऐसी ही मांगें बढ़ाएंगी। इससे राष्ट्रीय राजनीति में 'वोट के लिए मुफ्त' की संस्कृति गहरी होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेवड़ियों का बोझ बढ़ रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, राज्यों का सब्सिडी खर्च 2019–22 में 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया, जिसमें बिहार और पंजाब अग्रणी हैं। मुफ्त योजनाएं राज्यों के कर्ज को बढ़ा रही हैं, जिसका असर राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। रेवड़ियां संसाधनों को बुनियादी ढांचे और उत्पादक क्षेत्रों से हटाकर कल्याण योजनाओं में डाल रही हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने सुझाव दिया है कि ऐसी योजनाओं को सीमित किया जाए ताकि सड़क, रेल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़े। मुफ्त बिजली और नकद सहायता से ऊर्जा का दुरुपयोग और क्रेडिट संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, जो भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कठिन बना देता है। रेवड़ियों और लक्षित सब्सिडी में अंतर समझना जरूरी है। पीएम किसान और उज्ज्वला जैसी योजनाएं दीर्घकालिक लाभ देती हैं, जबकि रेवड़ियां केवल वोट लुभाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नीति आयोग, वित्त आयोग और आरबीआई की समिति बनाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा, चुनाव आयोग को वादों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सशक्त करना होगा। मतदाता जागरूकता भी जरूरी है, ताकि लोग अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता दें।

अभियान

ईश्वर अर्पण की परम साधना — भोग लगाने की दिव्य परंपरा और उसका आध्यात्मिक रहस्य

भोग अर्पण हिंदू धर्म की सबसे सुंदर, संवेदनशील और गूढ़ परंपराओं में से एक है। यह केवल पूजा-पद्धति का एक अंग नहीं, बल्कि यह वह क्षण है जब भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। भोग लगाना दरअसल केवल भोजन चढ़ाना नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की कृतज्ञता, प्रेम और समर्पण को मूर्त रूप देता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से ईश्वर को भोग लगाता है, तो वह यह स्वीकार करता है कि जीवन के हर सुख, हर साधन और हर अन्न का वास्तविक स्रोत स्वयं भगवान हैं। इसीलिए कहा गया है — "ईश्वर अर्पणं न त्यजेत्," अर्थात् जो कुछ मिले, वह पहले ईश्वर को समर्पित हो।

भोग लगाने की परंपरा का आधार अत्यंत पवित्र है। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसमें केवल भौतिक ऊर्जा नहीं होती, उसमें सूक्ष्म ऊर्जा भी निहित रहती है। जब हम वह भोजन पहले ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो उसकी ऊर्जा दिव्यता से स्पर्शित हो जाती है, और वही प्रसाद बनकर हमें वापस मिलती है। यह प्रसाद न केवल शरीर को पोषित करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसी कारण संस्कृत में भोग को "नैवेद्य" कहा गया है — जिसका अर्थ है "ईश्वर को अर्पण की गई वस्तु"।

भोग अर्पित करने से पहले भोजन को सात्विक, स्वच्छ और पूर्ण श्रद्धा के साथ तैयार करना अनिवार्य माना गया है। इस भोजन को कभी भी पहले चखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह केवल ईश्वर के लिए होता है। भोग को ऐसे पात्र में रखा जाना चाहिए जो केवल पूजा के लिए नियत हो — पीतल, चांदी या तांबे के बर्तन सबसे शुभ माने जाते हैं। लोहे या स्टील के बर्तनों में भोग अर्पित करना अशुभ माना गया है, क्योंकि ये धातुएँ ऊर्जात्मक दृष्टि से सकारात्मक तरंगें नहीं देतीं। भोग की थाली को सीधे जमीन पर रखने की भी मनाही है — उसे किसी लकड़ी के पाट या स्वच्छ आसन पर स्थापित करना चाहिए, जिससे अर्पण शुद्ध रहे।

अब यह प्रश्न आता है कि भोग ईश्वर के सामने कितनी देर रखा जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भोग को भगवान के समक्ष पाँच से दस मिनट तक रखना सर्वोत्तम है। इस दौरान भक्त का मन पूर्ण एकाग्र होना चाहिए। उसे केवल यह भाव रखना चाहिए कि — "हे प्रभु! यह आपका ही दिया हुआ अन्न है, मैं इसे आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप कृपा करके इसे स्वीकार करें।" इस समय सांसारिक विचारों, काम-काज या चिंताओं से मन को विराम देना चाहिए। कुछ परंपराओं में अधिकतम पंद्रह मिनट तक भोग रखने का विधान है, लेकिन इससे अधिक देर तक भोग को नहीं छोड़ना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति भोग को घंटों या पूरी रात तक ईश्वर के सामने रख देता है, तो वह प्रसाद अपनी पवित्रता खो देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय तक खुले वातावरण में रखे भोजन पर वायु के माध्यम से बाहरी ऊर्जा, धूल या नकारात्मक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। यह केवल भौतिक अशुद्धि नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक असंतुलन भी उत्पन्न करता है। इसलिए भोग को समय पर उठा लेना और आरती के साथ उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करना ही श्रेष्ठ माना गया है।

भोग लगाने की विधि में मंत्रोच्चार का भी अत्यंत महत्व है। श्रीहरि विष्णु को भोग अर्पित करते समय "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप, देवी लक्ष्मी के लिए "ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः" और भगवान शिव के लिए "ॐ नमः शिवाय" का उच्चारण अत्यंत शुभ फलदायक होता है। ये मंत्र केवल ध्वनि नहीं हैं, ये चेतन ऊर्जा के स्पंदन हैं, जो भोग को दिव्य स्पंदन प्रदान करते हैं। जब ये मंत्र वायु में गूंजते हैं, तो वातावरण में पवित्रता और शांति की तरंगें फैल जाती हैं।

भोग के साथ एक स्वच्छ जल का पात्र रखना चाहिए — यह केवल पूरक वस्तु नहीं, बल्कि प्रतीक है "जीवन के स्रोत" का। भोग को सदैव ढककर रखना चाहिए ताकि धूल या कीट उसमें न गिरें। भोग के बाद आरती करना और घंटी बजाना भी आवश्यक है। घंटी की ध्वनि केवल एक अनुष्ठानिक परंपरा नहीं है — यह उस ध्वनि ऊर्जा का संचार है जो नकारात्मक कंपन को दूर करके वातावरण को शुद्ध करती है।

भोग अर्पण का वास्तविक सार इस भाव में निहित है — "हे प्रभु! यह जो कुछ मैं अर्पित कर रहा हूँ, वह वस्तुतः मेरा नहीं, यह सब आपका ही दिया हुआ है। मैं केवल आपका पात्र हूँ, और यह अर्पण आपके प्रति मेरी कृतज्ञता का प्रतीक है।" जब यह भावना जागृत होती है, तब भोग केवल भोजन नहीं रहता — वह आत्मा की भक्ति बन जाता है। भोग लगाने का यह कार्य हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन की हर क्रिया में समर्पण का भाव जगाने की प्रक्रिया है। जब हम किसी वस्तु को ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो हम अपने भीतर के "अहं" को त्यागकर "मैं नहीं, केवल तुम" की भावना को जीते हैं। यही भावना हमें सच्ची शांति और दिव्यता के पथ पर अग्रसर करती है।

इसलिए जब भी आप भगवान को भोग अर्पित करें, उसे केवल परंपरा न समझें, बल्कि एक जीवंत संवाद के रूप में करें। ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं, केवल भाव बोलते हैं। जब भावना शुद्ध होती है, तो ईश्वर स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। और जब ईश्वर स्वीकार करते हैं, तो वही भोग हमारे जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का रूप लेकर लौटता है।

भोग लगाना इसलिए केवल पूजा नहीं — यह प्रेम की साधना है, आत्मा की कृतज्ञता है और ईश्वर से मिलने का एक सूक्ष्म माध्यम है। यही वह क्षण है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती — केवल समर्पण की ज्योति जलती है, और उसी में संपूर्ण जीवन का प्रकाश समाहित हो जाता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

7 अक्टूबर – विश्व कपास दिवस

गुजरात 23.71 लाख हेक्टेयर कपास बुवाई क्षेत्र, 71 लाख गांठ उत्पादन और 512 किग्रा प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता के साथ देश में दूसरे स्थान पर

▸▸गुजरात की अर्थव्यवस्था में कपास की भूमिका अहम, गुजरात की स्थापना से लेकर अब तक राज्य की कपास उत्पादकता में 373 किग्रा प्रति हेक्टेयर की वृद्धि

▸▸गुजरात द्वारा विकसित कपास की संकर-4 किस्म के बाद देश भर में शुरू हुए संकर कपास के दौर से भारत की कपास उत्पादकता में हुई भारी वृद्धि

गांधीनगर : रोटी, कपड़ा और मकान को मनुष्य जीवन की तीन आधारभूत आवश्यकता माना जाता है। रोटी के बाद महत्वपूर्ण आवश्यकता कपड़ा के लिए कपास अत्यंत जरूरी है। उसी कपास के महत्व को उजागर करने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को 'विश्व कपास दिवस' मनाया जाता है। 'सफेद सोना' के रूप में जाना जाने वाला कपास और गुजरात का नाता वर्षों पुराना है। गुजरात अनेक दशकों से कपास की खेती और अनुसंधान के मामले में जागरूक, प्रयासरत और अग्रणी रहा है।

भारत और गुजरात की अर्थव्यवस्था में कपास अत्यंत अहम भूमिका निभाता है। वर्ष 1960 में गुजरात की स्थापना के समय गुजरात की कपास उत्पादकता केवल 139 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो आज बढ़कर लगभग 512 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है, यह देश की औसत कपास उत्पादकता से अधिक है। इस आंकड़े से अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुसंधान, विस्तारीकरण, सरकार के किसान-उन्मुख दृष्टिकोण और किसानों के अथक प्रयासों के कारण राज्य को कपास के माध्यम से अरबों रूपए की आय हुई है, जो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी बात है।

> प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गत दो दशकों में कपास उत्पादन क्षेत्र में बदली गुजरात की तस्वीर
> -कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल

कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल ने कपास के संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जब भारत आजाद हुआ, तब सूती कपड़ों की ज्यादातर मिलें भारत में ही रह गईं जबकि कपास के बेहतर उत्पादन करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। नतीजतन, भारत में कच्चे माल की कमी के कारण हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करके विदेश से कपास आयात करना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में सूरत स्थित अनुसंधान फार्म के माध्यम से विकसित की गई कपास की हाइब्रिड यानी संकर-4 नामक किस्म के बाद देश भर में संकर कपास का नया युग शुरू हुआ और जल्द ही भारत की कपास उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप भारत की कच्चे माल की जरूरत तो पूरी हुई ही, साथ ही अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात भी होने लगा। वर्ष 2020-21 में भारत ने रिकॉर्ड 17,914 करोड़ रुपए मूल्य का कपास निर्यात किया।

कृषि मंत्री ने कहा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गत दो दशकों में कपास उत्पादन क्षेत्र में गुजरात की तस्वीर बदल गई है। उनके मजबूत नेतृत्व में हुए विभिन्न प्रयासों के कारण गुजरात में कपास का बुवाई क्षेत्र वर्ष 2001-02 तक 17.49 लाख हेक्टेयर था, वह 2024-25 तक बढ़कर 23.71 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसके साथ ही, कपास का उत्पादन भी 17 लाख गांठ से बढ़कर 2024-25 में 71 लाख गांठ और उत्पादकता 165 किग्रा प्रति हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 तक 512 किग्रा प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है।

कृषि मंत्री ने कहा कि गुजरात आज कपास के बुवाई क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। चालू वर्ष 2025-26 में अब तक राज्य के कुल 21.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुवाई हुई है और इस वर्ष भी कुल 73 लाख गांठ के उत्पादन का अनुमान है। आज गुजरात देश के कुल कपास बुवाई क्षेत्र में 20 फीसदी और कुल कपास उत्पादन में लगभग 25 फीसदी का योगदान देता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार की अनेक प्रोत्साहक योजनाओं और कपास संवर्धन के प्रयासों के चलते आने वाले समय में गुजरात देश भर में कपास उत्पादन का हब बनेगा और देश के कुल कपास उत्पादन में गुजरात का योगदान सबसे अधिक होगा।

कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल ने कहा कि बीटी कपास के दौर में भी पूरे देश में बीटी संकर किस्म विकसित करने और उसकी मान्यता प्राप्त करने में गुजरात अग्रणी रहा है। गुजरात सरकार के गहन प्रयासों से सार्वजनिक क्षेत्र की पहली दो बीटी संकर किस्मों - गुजरात कपास संकर-6 बीजी-2 और गुजरात कपास संकर-8 बीजी-2 को वर्ष 2012 में भारत सरकार की ओर से मान्यता मिली थी। इसके बाद, वर्ष 2015 में गुजरात ने दो और बीटी संकर किस्में - गुजरात कपास संकर-10 बीजी-2 और गुजरात कपास संकर-12 बीजी-2 विकसित कर किसानों को कपास की खेती के लिए बीटी कपास की चार किस्में उपलब्ध कराईं।

कृषि मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण भविष्य में प्राकृतिक रेशे, वस्त्रों, खाद्य तेल और पशु आहार के लिए कपास के बीज और खली की संभावित मांग आज के मुकाबले 2030 तक डेढ़ गुनी और 2040 तक दोगुनी होने की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन जरूरतों को ध्यान में रखकर गुजरात, अनुसंधान, नवीन और उन्नत विचारों तथा घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर कपास के निर्यात के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे सकता है।

पीडीईयू छात्र ने विकसित किया कम लागत वाला एआई-संचालित सिस्टम, जो इनडोर वायु को बनाएगा स्वच्छ

स्वास्थ्य तकनीक को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी (PDEU) के कंप्यूटर साइंस विभाग के अंतिम वर्ष के छात्र औम पंड्या ने एक कम लागत वाला, बुद्धिमान इनडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। यह नवाचार सटीक वायु मॉनिटरिंग की उच्च लागत की समस्या को दूर करता है, जिससे घरों और कार्यालयों में इसका उपयोग संभव हो जाता है।

कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. राजीव गुप्ता और पीएच.डी. शोधार्थी श्रीमती हितेश्री याग्निक के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए, औम ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो सस्ते सेंसरों का उपयोग करके सामान्य इनडोर प्रदूषकों, तापमान और आर्द्रता का पता लगाता है। इस आविष्कार का मुख्य आधार एक क्लाउड-आधारित मशीन लर्निंग मॉडल है। यह एआई-संचालित तकनीक रीयल-टाइम में सेंसर डेटा को कैलिब्रेट करती है, पर्यावरणीय कारकों की भरपाई करती है और अत्यंत सटीक एवं विश्वसनीय एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रीडिंग प्रदान करती है — जो आमतौर पर केवल महंगे उपकरणों में ही संभव होती है। इनडोर वायु प्रदूषण एक बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्या है, जो थकान से लेकर श्वसन संबंधी बीमारियों तक के कारणों से जुड़ी है। एक किफायती और सटीक मॉनिटरिंग उपकरण बनाकर, इस परियोजना ने लोगों को अपने वातावरण को समझने और समय रहते वायु गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता दी है।

औम वर्तमान में इस सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। उनका यह कार्य, जो कंप्यूटर साइंस और पर्यावरण इंजीनियरिंग के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, पीडीईयू में प्रोत्साहित किए जाने वाले अंतर्विषयक नवाचार की संस्कृति को दर्शाता है और यह दिखाता है कि छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए कितने प्रभावशाली समाधान विकसित कर सकते हैं।

भावनगर रेलवे मंडल पर स्वच्छता पखवाड़ा–2025 के अंतर्गत "स्वच्छ रेलगाड़ी" थीम पर विशेष अभियान का आयोजन

दिनांक 05.10.2025 एवं 06.10.2025 को स्वच्छता पखवाड़ा–2025 के अंतर्गत "स्वच्छ रेलगाड़ी" थीम पर विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में एवं वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री एस के मिश्रा के नेतृत्व में पोरबंदर, भावनगर एवं वेरावल कोचिंग डिपो में ५ ट्रेनों की गहन यांत्रिक सफाई (Intensive Mechanized Cleaning) अत्याधुनिक उपकरण द्वारा की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा–2025 के अंतर्गत आयोजित अभियान के दौरान कोचों के फर्श, शौचालय, खिड़कियाँ, दरवाजे तथा सीटों की मशीनों द्वारा स्वच्छता सुनिश्चित की गई। टीमों ने पर्यावरण अनुकूल सफाई सामग्री का उपयोग करते हुए यात्रियों को स्वच्छ एवं आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने का संकल्प लिया। साथ ही, स्टाफ को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया तथा "स्वच्छ रेल–स्वच्छ भारत" का संदेश दिया गया।

इस पहल से डिपो क्षेत्रों में स्वच्छता स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा रेल कर्मचारियों में कार्यस्थल स्वच्छ रखने की भावना को और बल मिला। इसके पश्चात स्वच्छता पखवाड़ा–2025 के तहत पोरबंदर, भवनगर एवं वेरावल स्टेशन पर यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किया गया जिसमे कैरेज एंड वैगन स्टाफ द्वारा बायो टॉयलेट के उपयोग संबंधी Do's and Don'ts समझाए गए तथा यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया।

7 अप्रैल 2026 तक भुज–पालनपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त

पश्चिम रेलवे द्वारा तकनीकी कारणों से भुज-पालनपुर-भुज इंटरसिटी एक्सप्रेस को अस्थाई तौर पर निरस्त किया गया है तथा गांधीधाम-पालनपुर-गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन यथावत समयानुसार चलेगी। विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 20928/20927 भुज-पालनपुर-भुज इंटरसिटी एक्सप्रेस 07 अप्रैल 2026 तक निरस्त रहेगी जबकि ट्रेन संख्या 19405/19406 गांधीधाम-पालनपुर-गांधीधाम एक्सप्रेस पूर्वत चलेगी। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन कर सकते है।

कंबोडिया से संचालित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, चार राज्यों में चला बड़ा अभियान

नई दिल्ली। साइबर अपराध की दुनिया में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ठगी गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जो कंबोडिया से बैठकर भारतीय नागरिकों की मदद से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी कर रहा था। दक्षिण-पश्चिमी जिला साइबर थाना पुलिस की टीम ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में एक साथ छापेमारी कर पांच आरोपियों — मंगू सिंह, हरि किशन सिंह, अक्षय, मुकुल और विक्रम — को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश का झांसा देकर लोगों को ऑनलाइन ग्रुप्स के माध्यम से फंसाता था।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के अनुसार, जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह कंबोडिया में बैठे साइबर संचालकों से सीधे जुड़ा था, जो टेलीग्राम के 'एटीपे' ग्रुप के जरिए भारत में सक्रिय सदस्यों को निर्देश भेजते थे। ठग पहले निवेशकों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ते, फिर शुरुआती निवेश पर छोटा लाभ दिखाकर भरोसा जीतते थे।

कंबोडिया में बैठकर भारतीयों की मदद से करते थे ठगी,पांच आरोपी हुए गिरफ्तार

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिमी जिला साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े बहुराज्यीय अभियान में उस साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश पर दोगुना फायदा देने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था। पुलिस ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में छापेमारी कर पांच आरोपियों — मंगू सिंह, हरि किशन सिंह, अक्षय, मुकुल और विक्रम — को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह कंबोडिया में सक्रिय साइबर नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि गिरोह निवेशकों को ऑनलाइन ग्रुप के जरिए झांसे में लेता था और विदेश से मिले निर्देशों पर काम करता था।

शिकायतकर्ता आर. चौधरी ने बताया कि उन्हें एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां ऊंचे मुनाफे का लालच देकर निवेश के लिए उकसाया गया। शुरुआत में आरोपियों ने छोटी रकम पर लाभ देकर भरोसा जीता और बाद में 10.7 लाख रुपये निवेश करवा लिए। जब चौधरी ने पैसे निकालने की कोशिश की तो भुगतान रोक दिया गया। इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक के नेतृत्व में एसआई चेतन राणा, हेड कांस्टेबल मनेंद्र और विजयपाल की टीम ने डिजिटल फुटप्रिंट, मनी ट्रेल और फर्जी खातों की जांच के आधार पर कार्रवाई की।

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर अपग्रेडेशन, कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर 25 नवंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक चल रहे अपग्रेडेशन कार्य के मद्देनजर पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

निरस्त होने वाली ट्रेनें:

1. 30 नवंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09043 बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी स्पेशल
2. 1 दिसंबर, 2025 से 5 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09044 बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल
3. 30 नवंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 05560 उधना-रक्सौल स्पेशल
4. 29 नवंबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें:

1. 29 नवंबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09189 मुंबई सेंट्रल-कटिहार स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर-कटनी मुरवारा-बीना

स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।

2. 25 नवंबर, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09190 कटिहार-मुंबई सेंट्रल स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया बीना-कटनी मुरवारा-मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
3. 25 नवंबर, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 04156 उधना-सूबेदारगंज स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया इटारसी-सतना-मानिकपुर-प्रयागराज स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
4. 01 दिसंबर, 2025 से 05 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 04155 सूबेदारगंज-उधना स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया प्रयागराज-मानिकपुर-सतना-इटारसी स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
5. 28 नवंबर, 2025 से 02 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद-दरभंगा स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया गुना-ग्वालियर-इटावा-कानपुर सेंट्रल स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
6. 01 दिसंबर, 2025 से 05 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल-इटावा-ग्वालियर-गुना स्टेशनों के रास्ते चलाई जायेगी।
7. 26 नवंबर, 2025 से 07 जनवरी, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 14320 बरेली-इंदौर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया ग्वालियर-गुना-बीना स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएगी।

आपदा में मिलकर काम करेंगे तीन एजेंसियां दिल्ली में समझौता पत्र पर हुआ हस्ताक्षर

नई दिल्लीः रेलवे सुरक्षा बल (RPF), भारतीय रेल आपदा प्रबंधन संस्थान (IRIDM) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के बीच आज नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का उद्देश्य रेल सुरक्षा बल को प्रशिक्षित 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स' बल के रूप में तैयार करना है जो आपदा के गोल्डन आवर में त्वरित बचाव और राहत कार्य कर सके। यह साझेदारी रेल सुरक्षा को एक नई दिशा प्रदान करेगी और आपदा प्रबंधन में भारतीय रेल की क्षमता को और सशक्त बनाएगी। इस अवसर पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला, IRIDM के निदेशक वी. वी. एस. श्रीनिवास तथा जगजीवन राम रेल सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ के निदेशक बी. वेंकटेश्वर राव ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता के तहत RPF कर्मियों को NDRF बटालियन में लघु-अवधि के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। जिनमें आपदा प्रतिक्रिया, खोज एवं बचाव, बाढ़/जल-आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और संयुक्त अभ्यास जैसे विषय शामिल होंगे। इसके बाद IRIDM, बेंगलुरु में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जहां RPF और NDRF कर्मी एक साथ भाग लेंगे। MoU के अंतर्गत JR RPF अकादमी, लखनऊ को प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है। यह कार्यक्रम पूरे देश में रेलवे सुरक्षा विशेष बल के लिए लागू होगा। इसके माध्यम से आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र में RPF एवं NDRF के बीच एक सुदृढ़ सहयोग ढाँचा तैयार होगा, जो देश भर में रेल यात्रियों की सुरक्षा को एक नई ऊँचाई पर ले जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर स्थित दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में गरिमामय ढंग से मनाई गई भारतीय वायु सेना की 93वीं वर्षगांठ

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में सोमवार को गांधीनगर स्थित दक्षिण पश्चिमी वायु कमान (एसडब्ल्यूएसी-स्वैक) मुख्यालय में भारतीय वायु सेना की 93वीं वर्षगांठ गरिमामय ढंग से मनाई गई।

मुख्यमंत्री ने इस कमान के वायु सैनिकों सहित एयर फोर्स परिवार को 93वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय वायु सेना ने हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय वायु सेना का पिछला दशक स्वर्णिम दशक बना है।

उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु सेना ने अपनी कार्यकुशलता और दक्षता से दुनिया को जिस साहस और पराक्रम का परिचय दिया है, उस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष मिशन पूरा कर जो बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, वह वायु सेना की इस 93वीं वर्षगांठ को एक विशेष गौरव प्रदान करने वाली घटना है।

> प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु सेना ने दुनिया को अप्रतिम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया
> -मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

श्री भूपेंद्र पटेल ने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान की सराहना करते हुए कहा कि वह वायु सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक दायित्व में भी योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ मां के नाम, फिट इंडिया मुवमेंट और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसे सामाजिक अभियानों में 'स्वैक' सक्रिय भागीदार रहा है। उन्होंने वायु सेना परिवार की महिलाओं द्वारा संचालित 'संगिनी' संगठन की सामाजिक और कल्याणकारी कार्यों की पहल की भी प्रशंसा की।

दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल श्री नागेश कपूर ने स्वागत भाषण के माध्यम से मुख्यमंत्री का स्वागत किया और वायु सेना की वर्षगांठ की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला।

समारोह में मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर श्री एस. श्रीनिवास सहित वायु सेना के अधिकारी, वायु सैनिक और उनके परिवारजन शामिल हुए। एयरफोर्स बैंड की सुमधुर धुनों ने समारोह को शौर्य और उत्साह से भर दिया।

7.4 करोड़ मतदाता चुनेंगे नई सरकार — बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, महिला मतदाताओं के मुकाबले तीन गुना बढ़े पुरुष वोटर

पटना। बिहार की सियासत एक बार फिर जोश और उत्साह से सराबोर होने जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार राज्य में दो चरणों में मतदान होगा — पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद यह साफ हो गया है कि इस बार करीब 7 करोड़ 41 लाख से अधिक मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर नई सरकार का चयन करेंगे। बिहार में मतदाताओं की यह सूची एसआईआर के बाद जारी हुई है, जिसमें कई रोचक परिवर्तन सामने आए हैं। जहां नए मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं मृतक, दोहरी प्रविष्टि या राज्य से स्थायी रूप से बाहर जा चुके मतदाताओं के नाम हटाने के बाद कुल संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। एसआईआर से पहले राज्य में 7.89 करोड़ मतदाता थे, जबकि संशोधित सूची में यह संख्या घटकर 7.41 करोड़ रह गई। यानी लगभग 47.77 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इनमें से 22 लाख से अधिक लोग ऐसे थे जिनका निधन हो चुका था, करीब सात लाख दोहराए गए नाम थे और 36 लाख से अधिक लोग स्थायी रूप से बिहार छोड़ चुके थे।

चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार पुरुष मतदाताओं की संख्या में तीन गुना तेजी से वृद्धि हुई है।

2020 के विधानसभा चुनावों में जहां 3.87 करोड़ पुरुष मतदाता थे, वहीं इस बार यह संख्या बढ़कर 3.92 करोड़ हो गई है। महिलाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अपेक्षाकृत कम — 2020 में 3.48 करोड़ महिलाओं के मुकाबले इस बार 3.49 करोड़ महिला मतदाता वोट डालने के लिए पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

युवा मतदाताओं की भूमिका इस चुनाव में निर्णायक मानी जा रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 18-19 वर्ष आयु वर्ग के 14 लाख 1 हजार 150 मतदाता हैं, जबकि 20 से 29 वर्ष के बीच के 1.63 करोड़ युवा अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही राज्य में 7 लाख 20 हजार से अधिक दिव्यांग मतदाता भी हैं, जिनके लिए आयोग ने विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की है।

इस बार 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं — जिनमें 13,911 शहरी और 76,801 ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। हर केंद्र पर औसतन 818 मतदाता वोट डालेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेब कास्टिंग की जाएगी ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आयोग ने बताया कि 292 केंद्रों का संचालन दिव्यांग अधिकारियों, 38 केंद्रों का संचालन युवा अधिकारियों और 1,044 केंद्रों का संचालन महिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए आयोग ने विशेष सुविधाएँ सुनिश्चित की हैं। भूतल पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहाँ रैंप, व्हीलचेयर और प्रशिक्षित वालंटियर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो लोग स्वास्थ्य या शारीरिक असमर्थता के कारण घर से मतदान करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है — इसके लिए उन्हें 12D फॉर्म भरना होगा।

चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए 8.5 लाख चुनाव कर्मियों की तैनाती की जा रही है। इनमें 4.53 लाख मतदान कर्मी, 9,600 सेक्टर अधिकारी, 17,800 सूक्ष्म पर्यवेक्षक, 28,300 मतगणना अधिकारी, 4,800 मतगणना सूक्ष्म पर्यवेक्षक, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएँ शामिल होंगी।

बिहार चुनाव की यह तैयारियाँ न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि लोकतांत्रिक परंपरा के उस गहरे विश्वास की झलक भी पेश करती हैं जो भारतीय गणराज्य की आत्मा में बसी है। जब 7.4 करोड़ से अधिक लोग 6 और 11 नवंबर को मतदान के लिए कतार में खड़े होंगे, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जनता के विश्वास का उत्सव होगा — जहाँ हर वोट बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा।

श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात की अविरत विकास यात्रा के सफल 24 वर्ष पूर्ण

विकास सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम :-

- मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी लेंगे 'भारत विकास प्रतिज्ञा', साथ ही सरकारी कार्यालयों, स्कूल-कॉलेजों और ऑनलाइन माध्यम से भी ली जाएगी प्रतिज्ञा
- साबरमती रिवरफ्रंट में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रदर्शनी
- ऑनलाइन क्विज और निबंध प्रतियोगिता, व्याख्यान माला, पदयात्रा तथा प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम- 'नमोत्सव' का आयोजन
- रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम
- 1 से 25 करोड़ रुपए तक के 3,326 करोड़ रुपए के कार्य

राज्य की 24 वर्षों की संकल्प सिद्ध की गाथा को जन-जन के बीच उजागर करने के लिए 7 से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह का शानदार आयोजन
-प्रवक्ता मंत्री श्री ऋषिकेश

गांधीनगर : प्रवक्ता मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। 7 अक्टूबर, 2001 से शुरू हुई गुजरात के विकास की अविरत यात्रा 7 अक्टूबर, 2025 को सफलतापूर्वक 24 वर्ष पूरे कर रही है।

इसके अंतर्गत, गुजरात की संकल्प सिद्धि की इस बहुआयामी विकास यात्रा और जनहितकारी सुशासन की गाथा को जन-जन के बीच उजागर करने के लिए 7 से 15 अक्टूबर के दौरान पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ 'विकास सप्ताह' मनाया जाएगा।

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि इस विकास सप्ताह के दौरान कुल 10 विभागों की प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ 13 विषयों को शामिल किया गया है और प्रत्येक दिवस को अलग-अलग थीम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान युवा, महिला और किसान सहित राज्य के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आयोजन किया गया है। इस आयोजन में लोगों को विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ-साथ विकासात्मक कार्यों से लाभान्वित भी किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष विकास सप्ताह के दौरान राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत विधानसभा प्रांगण में मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में भारत विकास प्रतिज्ञा ली जाएगी। इसी समय, राज्य के 34 जिलों में भी कलेक्टर कार्यालय एवं अन्य सरकारी कार्यालयों, स्कूल-कॉलेजों में 'भारत विकास प्रतिज्ञा' ली जाएगी। इस प्रतिज्ञा को व्यापक स्वरूप पर ले जाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि माईगव (My.Gov) पोर्टल पर बड़ी संख्या में ऑनलाइन प्रतिज्ञा ले सकें। इस कार्यक्रम के द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल विकास सप्ताह की औपचारिक शुरुआत करेंगे।

07-10-2025
युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि 7 से 15 अक्टूबर के दौरान अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रदर्शनी, पूरे राज्य में ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, स्कूलों और कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, व्याख्यान माला, महत्वपूर्ण स्थलों पर पदयात्रा, प्रतिदिन 'नमोत्सव' सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा के साथ पॉडकास्ट, वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में 1000 से अधिक छात्र भाग लेंगे, जहां विकसित भारत@2047 के संकल्प को पूर्ण करने के लिए युवाओं की सहभागिता विषय पर चिंतन-मंथन किया जाएगा। इसके अलावा, पूरे सप्ताह के दौरान 50 अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आत्मनिर्भर भारत

प्रवक्ता मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों और सहकारिता क्षेत्र को पहुंचाए गए लाभों के लिए सहकारी संस्थानों के सभासदों द्वारा प्रधानमंत्री को एक करोड़ से अधिक पोस्टकार्ड के जरिए श्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 7 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

प्रधानमंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन में देश के विकास के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों से अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे सामाजिक और आर्थिक लाभ तथा देश में आए बदलाव के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सहकारिता विभाग द्वारा 1 करोड़ से अधिक पोस्टकार्ड तैयार किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत, गर्व से कहो स्वदेशी है, आयुष्मान भारत, वित्तीय समावेशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और सोलर रूफटॉप योजना तथा 22 सितंबर से लागू किए गए जीएसटी सुधार जैसे विभिन्न विषयों पर पोस्टकार्ड लिखे गए हैं।

उल्लेखनीय है कि डाक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 1.50 करोड़ पोस्टकार्ड छापे जाते हैं, जबकि केवल गुजरात में सहकारिता क्षेत्र एवं शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही अल्पकाल में 1 करोड़ से अधिक पोस्टकार्ड लिखे गए हैं, जो कि एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।

7 अक्टूबर को अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवरफ्रंट में पोस्टकार्ड प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसे नागरिक देख सकते हैं।

इसके अलावा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जरिए भी राज्य के अलग-अलग कॉलेजों के छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान, ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी क्रांति और भारत को अग्रणी बनाने की पहल का स्वागत करते हुए पोस्टकार्ड के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। जिसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कुल 4.50 लाख पोस्टकार्ड लिखे गए हैं।

इसके अतिरिक्त, स्वदेशी अभियान के अंतर्गत 100 कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया है, जिनमें से 62 व्याख्यान पूरे हो चुके हैं। जिनमें विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा छात्रों को यह बताया गया है कि कैसे स्वदेशी अपनाने से राज्य और राष्ट्र को समृद्ध एवं उत्कृष्ट बनाया जा सकता है।

08-10-2025
रोजगार मेला कार्यक्रम

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि गांधीनगर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही अन्य 33 जिलों में भी राज्यव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

जिनमें 50 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा, 25 हजार से अधिक आईटीआई छात्रों को प्रोविजनल प्लेसमेंट ऑफर पत्रों का वितरण भी किया जाएगा।

इतना ही नहीं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के लिए उद्योगों के साथ 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

09-10-2025 और 10-10-2025
मेहसाणा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस

प्रवक्ता मंत्री ने बताया कि मेहसाणा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत एमएसएमई कॉन्क्लेव, उद्यमिता सहायता मेला, वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक, क्षेत्रीय पुरस्कार, अग्रणी उद्योगपतियों, बिजनेस लीडरों और युवाओं की अपनी विकास यात्रा के अनुभवों तथा ये क्षेत्र विकसित गुजरात@2047 के विजन में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, इस पर चर्चा, स्टार्टअप हैकाथॉन, स्टार्टअप द्वारा पिचिंग सेशन और उद्यमियों द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

11 अक्टूबर, 2025

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजकोट में आयोजित होगा। इस विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभों का वितरण, पंचायत उन्नति सूचकांक के बारे में मार्गदर्शन, विभिन्न योजनाओं के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों का सम्मान, ग्राम गृह निर्माण बोर्ड से जुड़ी घोषणाएं, राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत घर (भवन) का सामूहिक शिलान्यास किया जाएगा।

इसके अलावा, 15-10-2025 को रथयात्रा समापन के समय प्रत्येक जिले में 1 करोड़ से कम राशि वाले कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सूचना एवं प्रसारण विभाग के सहयोग से प्रति जिला एक विकास रथ का आयोजन तथा सभी सरकारी संस्थाओं में 'स्वच्छता शपथ' दिलाई जाएगी।

12 एवं 13 अक्टूबर, 2025
राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि इस दिन नगर पालिकाओं के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम, स्वदेशी मेला (शॉपिंग फेस्टिवल) का आयोजन, सभी महानगर पालिकाओं में स्थानीय कलाकारों के सहयोग से रिसाइकल की गई वस्तुओं का उपयोग कर सार्वजनिक स्थापत्य का निर्माण और सभी महानगर पालिकाओं के प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाना जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

14 अक्टूबर, 2025
कृषि विकास दिवस/ रबी कृषि महोत्सव

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि राज्य व्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ, रबी कृषि महोत्सव के अंतर्गत फसल परिसंवादों एवं किसान मार्गदर्शन, कृषि प्रदर्शनी, पशु स्वास्थ्य मेले, नई टेक्नोलॉजी आधारित प्रदर्शनी-स्टॉल जैसी अनेक किसान-उन्मुख गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

15 अक्टूबर, 2025
शिलान्यास एवं लोकार्पण के कार्यक्रम

प्रवक्ता मंत्री ने बताया कि गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में लोकार्पण एवं शिलान्यास का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक के 3326 करोड़ रुपए के कार्य शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 7 से 15 अक्टूबर के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा भी हैकाथॉन, निबंध प्रतियोगिता, भित्ति चित्र, क्विज स्पर्धा, 100 व्याख्यान माला, वेबिनार वर्कशॉप और रिसर्च पेपर, यूनिवर्सिटी में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के सेमिनार तथा दस 'स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टडी सेंटर' का लोकार्पण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग

विकास सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उच्च जोखिम वाले प्रसव के लक्षणों वाली लगभग 1700 गर्भवती माताओं की पहचान करेगा, उन्हें बर्थ माइक्रो प्लान के बारे में समझाएगा, नमोश्री योजना के अंतर्गत लगभग 10,000 लाभार्थियों का पंजीकरण और डीबीटी के जरिए लगभग 7 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 6000 से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।

इसके अलावा, वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक उम्र के 14,000 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण, विकास सप्ताह के दौरान स्थानीय विधायकों और पदाधिकारियों द्वारा टीबी के निदान के लिए 180 टूनैट मशीनों के लोकार्पण कार्यक्रम, राज्य के 24 मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) प्रशिक्षण का आयोजन, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन, प्रति जिला एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सहित कुल 34 मॉडल सीएचसी बनाने का संकल्प, पॉडकास्ट के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान (एसएनएसपीए) के तहत किए गए कार्यों का ई-बुक के माध्यम से लॉन्चिंग किया जाएगा।

प्रवक्ता मंत्री ने बताय कि इस सप्ताह के दौरान सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा '24 वर्ष सफल और सक्षम नेतृत्व के' शीर्षक वाली एक पुस्तिका का प्रकाशन, माईगव (My.Gov.India) पोर्टल पर विकास सप्ताह क्विज कंपीटिशन का आयोजन और इसी पोर्टल पर फोटो और रील कंपीटिशन का आयोजन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सीजेआई गवई से की बात — बोले, हमले से हर भारतीय आहत, समाज में ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति बी. आर. गवई से बातचीत कर सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए जूता फेंकने के प्रयास की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हमले से न केवल न्यायपालिका बल्कि पूरा देश आहत है। उन्होंने इस घटना को भारतीय समाज और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध बताया और कहा कि "हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा — "भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज है। हमारे समाज में ऐसे भर्त्सनायोग्य कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की सराहना करता हूं। यह हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने और न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

यह घटना सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में उस समय घटी जब अदालत की कार्यवाही जारी थी। 71 वर्षीय एक वकील ने अचानक अपनी सीट से उठकर प्रधान न्यायाधीश गवई की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे रोक लिया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अदालत के अंदर मौजूद लोगों ने इस कृत्य से गहरा आक्रोश व्यक्त किया। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि आरोपी की पहचान राकेश किशोर नामक वकील के रूप में हुई है। उसके पास से एक नोट बरामद हुआ, जिस पर लिखा था — "सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।" फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) ने इस घटना को न्यायपालिका की गरिमा पर आघात बताते हुए आरोपी वकील का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। परिषद ने कहा कि किसी भी असहमति या विचार-विमर्श का स्थान न्यायिक संस्थान के भीतर इस प्रकार की हिंसक हरकतें नहीं हो सकतीं।

प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई ने घटना के तुरंत बाद अदालती कार्यवाही रोकने के बजाय अत्यंत संयम और शालीनता का परिचय दिया। उन्होंने अदालत में मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों से कहा — "इसे नजरअंदाज करें।" उन्होंने यहां तक कहा कि आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। उनका यह व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा और सहिष्णुता का उदाहरण बन गया।

इस पूरे घटनाक्रम ने देशभर में बहस छेड़ दी है। कानूनी विशेषज्ञों, पूर्व न्यायाधीशों और राजनीतिक नेताओं ने एकमत से कहा है कि न्यायालय जैसी पवित्र संस्था में इस प्रकार की घटना लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार इस तरह की हरकतों के प्रति बिल्कुल शून्य-सहनशीलता का रुख रखती है।

सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई यह घटना भले ही कुछ ही क्षणों की रही हो, लेकिन इसने देश को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि न्यायपालिका की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा केवल अदालत की दीवारों से नहीं, बल्कि नागरिक चेतना से भी होती है — और जब प्रधान न्यायाधीश स्वयं संयम और क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।

ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन से होगी सख्त पूछताछ

नई दिल्ली। सस्पेंड आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच तेज हो गई है। ईडी ने उनके करीबी सहयोगी और कारोबारी निकांत जैन को एक बार फिर पूछताछ के लिए समन जारी किया है। बताया जा रहा है कि जमानत पर रिहा होने के बाद से निकांत लगातार फरार चल रहा है और एजेंसी को उसकी तलाश है। ईडी ने इस मामले से जुड़े कई वित्तीय लेन-देन, संपत्ति खरीद और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का पता लगाया है, जिनसे कई और नाम सामने आने की संभावना है।

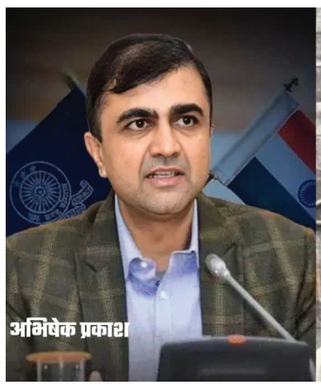

मामले की शुरुआत उस समय हुई जब यूपी में सोलर संयंत्र लगाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि विश्वजीत ने निकांत जैन के खिलाफ गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि निकांत ने तत्कालीन इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश के कहने पर उनसे कमीशन की मांग की थी। इस आरोप के बाद निकांत की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया। ईडी ने 7 अगस्त को निकांत के पांच ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापों में कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले, जिनसे संकेत मिला कि निकांत ने अपने और अपने परिवार के नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई है। जांच में यह भी सामने आया है कि निकांत ने कुछ जमीनें अपने भाई सुकांत जैन और अन्य सहयोगियों के नाम पर खरीदी थीं ताकि धन के स्रोत को छिपाया जा सके। अब ईडी इन संपत्तियों के असली मालिकाना हक की जांच कर रही है।

ईडी सूत्रों का कहना है कि एजेंसी को निकांत की कंपनी और उससे जुड़ी फर्मों के लेन-देन की पूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के जरिये कथित रिश्वत की रकम को सफेद किया गया था। इसके अलावा, निकांत के कारोबारी साथी सौरभ सेठ के घर से बरामद दस्तावेजों में कई अहम सुराग मिले हैं, जिन पर ईडी जल्द कार्रवाई कर सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी को यह भी शक है कि यह नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है बल्कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। निकांत के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ताकि वह देश से बाहर न जा सके।

ईडी के अधिकारियों का कहना है कि अगर निकांत ने इस बार भी पूछताछ में हाजिर होने से परहेज किया, तो उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं, जो सरकारी पदों का दुरुपयोग कर धन अर्जित करने के आरोपों में फंसे हुए हैं। सरकारी हलकों में इस मामले ने हलचल मचा दी है। अभिषेक प्रकाश पहले ही सस्पेंड हैं और अब उनके करीबी सहयोगी की बढ़ती मुश्किलें संकेत दे रही हैं कि ईडी आने वाले दिनों में इस भ्रष्टाचार कड़ी को पूरी तरह उजागर करने के लिए व्यापक कार्रवाई करने जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब, निवेशकों की गुम परिसंपत्तियों पर बनेगा केंद्रीकृत पोर्टल?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक पहलू से जुड़े मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से जवाब मांगा है। यह मामला उन करोड़ों निवेशकों और जमाकर्ताओं से जुड़ा है जिनकी वित्तीय परिसंपत्तियाँ — जैसे बैंक जमा, म्यूचुअल फंड, बीमा राशि, शेयर या बॉन्ड — वर्षों से अप्राप्त या अनक्लेम्ड पड़ी हुई हैं। अनुमान है कि ऐसी परिसंपत्तियों की कुल राशि करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये है।मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे निवेशकों को उनकी वैध संपत्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ठोस तंत्र की आवश्यकता है। अदालत ने इस संबंध में केंद्र और अन्य नियामक संस्थाओं को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि देशभर में लाखों छोटे निवेशक और जमाकर्ता अपनी जमा राशियों के हकदार हैं, लेकिन अलग-अलग संस्थाओं और बैंकों में यह जानकारी बिखरी होने के कारण वे अपनी परिसंपत्तियाँ प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार खाताधारक के निधन के बाद परिजन इस धन की जानकारी तक नहीं रख पाते, जिससे यह राशि सरकारी या संस्थागत खातों में पड़ी रह जाती है।

याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को निर्देश दे कि एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल बनाया जाए, जहाँ व्यक्ति केवल अपने पैन कार्ड, आधार या अन्य पहचान विवरण डालकर यह पता लगा सके कि उसकी कोई वित्तीय संपत्ति किसी संस्था में अप्राप्त तो नहीं है। इस पोर्टल से निवेशक सीधे क्लेम भी दाखिल कर सकेंगे।

इस याचिका ने सरकार और नियामक एजेंसियों के सामने एक बड़े आर्थिक सुधार की संभावना खोल दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा केंद्रीकृत पोर्टल बनता है तो यह न केवल निवेशकों की पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि देश की वित्तीय प्रणाली को अधिक संगठित और जवाबदेह भी बनाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला "सार्वजनिक हित" से जुड़ा हुआ है और इसे गंभीरता से देखा जाएगा। अदालत अब इस पर चार हफ्ते बाद विस्तृत सुनवाई करेगी, जिसके बाद यह तय किया जा सकता है कि भारत में निवेशकों की गुम परिसंपत्तियों के लिए एक एकीकृत प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाया जाए या नहीं।

धनतेरस और दिवाली से पहले सोने की रिकॉर्ड उड़ान, 10 ग्राम का भाव पहुंचा 1.3 लाख रुपये के पार

मुंबई। त्योहारी सीजन और शादी-ब्याह के दौर से ठीक पहले सोने की कीमतों ने इतिहास रच दिया है। सोमवार को देशभर के सर्राफा बाजारों में सोने के भावों में जबरदस्त उछाल देखा गया। 10 ग्राम सोने का दाम 9,700 रुपये बढ़कर 1,30,300 रुपये के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस अप्रत्याशित तेजी ने आम उपभोक्ताओं से लेकर ज्वेलर्स तक को चौंका दिया है।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव शुक्रवार को 1,20,600 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो सोमवार को बढ़कर 1,30,300 रुपये हो गया। यानी महज तीन दिनों में सोना लगभग 10,000 रुपये महंगा हो गया। इस साल के भीतर ही सोने की कीमतों में 51,000 रुपये यानी लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। दिसंबर 2024 में यही सोना 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।

स्थानीय बाजारों में भी यह बढ़ोतरी साफ नजर आई। दिल्ली और मुंबई के सर्राफा मंडियों में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,700 रुपये की उछाल के साथ 1,22,700 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं, चांदी की चमक भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हुई। सफेद धातु की कीमतों में 7,400 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इसका भाव 1,57,400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी यही रुख देखने को मिला। न्यूयॉर्क और लंदन में सोने की कीमत करीब 2 प्रतिशत बढ़कर 3,949.58 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। वहीं, चांदी भी 1 प्रतिशत बढ़कर 48.75 डॉलर प्रति औंस पर पहुंची। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर की मजबूती के बावजूद अमेरिकी शटडाउन की स्थिति और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में बुलियन यानी सोने की ओर रुख कर रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी के अनुसार, "सोना इस समय महंगाई से बचाव का सबसे विश्वसनीय साधन बन चुका है। निवेशक ऊंचे दामों के बावजूद इसमें भरोसा जता रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की अस्थिरता, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव सोने की तेजी के मुख्य कारण हैं।"

इसी तरह, कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कायनात चैनवाला ने बताया कि अमेरिकी सरकार का शटडाउन अब छठे दिन में प्रवेश कर गया है, जिससे निवेशकों के बीच चिंता बढ़ी है। इसके चलते सोना पहली बार 3,940 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गया। उन्होंने कहा कि "सरकारी ठहराव से अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ने की आशंका है, और यही स्थिति सोने की मांग को और बढ़ा रही है।"

एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट जतीन त्रिवेदी के अनुसार, "भारत में इस समय दोहरी तेजी का असर है — एक ओर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें चढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर त्योहारी मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में सोने की खरीद तेज हुई है। रुपया कमजोर हुआ है, जिससे कीमतें और उछल रही हैं।"

उत्तराखंड में ठंड की पहली दस्तक, बदरीनाथ-केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में गिरी सीजन की पहली बर्फ

रुद्रप्रयाग/चमोली। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। सोमवार को बदरीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की पर्वत चोटियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पूरे राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है। बर्फ के फाहे गिरते ही श्रद्धालुओं के चेहरों पर रौनक लौट आई, जबकि स्थानीय लोगों ने सर्दियों की शुरुआत का एहसास कर लिया। केदारनाथ धाम में सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे अचानक आसमान में बादल छा गए और कुछ ही देर में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। धीरे-धीरे बर्फ की परतें मंदिर परिसर और आसपास की पहाड़ियों को सफेद चादर से ढकने लगीं। पूरा क्षेत्र अद्भुत दृश्य में बदल गया। ठंड बढ़ने के बावजूद श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारों में डटे रहे और बर्फबारी के बीच "हर हर महादेव" के जयकारों से घाटी गूंज उठी। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि 7 अक्टूबर से उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और कई जिलों में बारिश की संभावना है। विभाग ने बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री

और हेमकुंड क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि यात्री ऊनी कपड़े, रेनकोट और आवश्यक दवाएं साथ रखें ताकि ठंड और फिसलन से बचाव किया जा सके। बदरीनाथ धाम में भी सोमवार दोपहर के बाद मौसम ने रुख बदला। नर नारायण पर्वत, उर्वशी पर्वत, माणा गांव और आसपास की ऊंची चोटियों पर सफेद बर्फ की परत जमने लगी। बर्फबारी के साथ तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई और हवा में ठंडक बढ़ गई। बदरीनाथ धाम के आसपास का दृश्य ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने खुद अपनी रंगत बदल ली हो।